

# भविष्य से समझौता

साभार : इंडियन एक्सप्रेस

28 अक्टूबर, 2017

कपिल सिब्बल

(वरिष्ठ कांग्रेस नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री)

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-III ( भारतीय अर्थव्यवस्था ) के लिए महत्वपूर्ण है।

प्रकल्पित क्षति कार्रवाई योग्य हैं वास्तविक क्षति नहीं। हांलाकि, यह पुरानी है लेकिन सच है। ऐसा प्रतीत होता है कि विमुद्रीकरण के कारण 2,50,000 करोड़ रुपये का नुकसान उठाना जरूरी नहीं है, क्योंकि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सीएजी) का कहना है कि वह नीतिगत निर्णयों के खिलाफ नहीं जा सकते। इसके अलावा, कतारों में खड़े रहने वाले 100 से अधिक लोगों के लिए किसी को जिम्मेदार नहीं माना गया, जिससे उन लोगों को भी न्याय नहीं मिल सका या दोषियों की पहचान नहीं की जा सकी, जो चिकित्सकीय आपात स्थितियों में नकदी की कमी के कारण अपने लोगो को खो चुके हैं। लेकिन उनके पूर्ववर्तियों ने न केवल स्पेक्ट्रम और कोयला ब्लॉकों की नीलामी के नीतिगत निर्णय पर सवाल उठाया, बल्कि कथित संभावित नुकसान के आंकड़ों को भी मिटा दिए। लेखक के अनुसार संस्थागत पदों में परिवर्तन सीएजी के परिवर्तन के साथ होता है। लोग जो करते हैं उससे संस्थाओं को कोई फर्क नहीं पड़ता। यही कारण है कि हम अक्सर राष्ट्रीय जांच एजेंसी और सीबीआई के दोहरे बर्ताव के मूक दर्शक बन कर रह जाते हैं, जो राजनीतिक स्वामियों को खुश करने की इच्छा रखते हैं।

हम अपनी अर्थव्यवस्था की स्थिति, विशेष रूप से बैंकों की बढ़ती गैर निष्पादित परिसंपत्तियों पर सिर्फ विलाप कर के रह जाते हैं। इसका श्रेय न्यायपालिका को अपने विनाशकारी आर्थिक परिणामों से अनजान होने के कारण और सभी तरह के दूरसंचार लाइसेंस और कोयला ब्लॉक आवंटन के रद्द करने के फैसले जाता है। सरकार को स्पेक्ट्रम और कोयला ब्लॉकों को नीलामी करना पड़ा, क्योंकि इस तरह के प्राकृतिक संसाधनों से निपटने के कोई भी अन्य तरीके से इसे अदालत के गुस्से का सामना करना पड़ेगा। सीएजी ने, सद्गुण की आकृति को व्यक्त करते हुए, अपने आप को यह आश्चर्य किया कि अगर प्रतिस्पर्धी बोली के बिना प्राकृतिक संसाधनों को आवंटित किया जाता है तो सरकारी खजाने को नुकसान होगा। 'निष्पादन लेखापरीक्षा' के परिधान के तहत, उन्होंने संहारक हानि की अवधारणा को विकसित करके, जो यूपीए की अपनी विश्वसनीयता को कम करते हैं, विकसित किया। परिणामस्वरूप 2जी स्पेक्ट्रम के पांच मेगा हर्ट्ज को 1,651 करोड़ रुपये में आवंटित किया गया, जिसकी नीलामी 2012 में 14,000 करोड़ रुपये के आधार मूल्य पर की गई थी। स्पेक्ट्रम की कमी से दूरसंचार ऑपरेटर्स को बचाने के लिए बोली लगाने की जरूरत थी। अवसंरचना में निवेश के लिए आवश्यक पूंजी में ऋण का निर्वहन किया गया। बैंक पहले से ही भारी ऋणों के लिए ऑपरेटर्स को उधार देने के लिए तैयार नहीं थे और निवेश पर लौटते हुए सेवा बढ़ते कर्ज के लिए अपर्याप्त था।

आठ साल बाद, यह क्षेत्र लगभग 5 लाख करोड़ रुपये के कर्ज के नीचे दबे हुए है (बैंकिंग क्षेत्र में यह 7.29 लाख करोड़ रुपये है)। टेलीनॉर, इटिस्लाट और सिस्तेमा इससे बाहर निकल गए। वोडाफोन और आइडिया का मर्ज करने का इरादा है और टाटा टेलीकॉम, एक तरह से एयरटेल को भेट के तौर पर दिया गया है। रिलायंस गहरी परेशानी में है, एयरसेल-रिलायंस समझौता असफल हो गया। बाहर निकलने के अलावा रिलायंस का कोई विकल्प नहीं बचा है। इसलिए हमारे पास सिर्फ तीन खिलाड़ी बचे हैं: जियो, एयरटेल और वोडाफोन/आइडिया। हमारे विस्तृत नियामक की प्रकृति को देखते हुए वोडाफोन अपने प्रदर्शन को और अधिक बढ़ा नहीं सकता। स्पेक्ट्रम का आवंटन प्रतियोगिता को प्रोत्साहन देने के लिए बुनियादी ढांचे में निवेश के लिए अधिशेष छोड़ रहा है और नीलामी ने उस कहानी को उकसाया है।

बिजली, स्टील, सीमेंट और फेरोअलॉयल को कोयले की जरूरत है। घरेलू मांग को पूरा करने के लिए कोल इंडिया पर्याप्त उत्पादन नहीं कर पाता। राज्यों को इन क्षेत्रों में निवेश करना चाहिए, लेकिन कोयले की टोस और पर्याप्त आपूर्ति के बिना, हितधारक निवेश करने में संकोच करते हैं। जिनमें भी त्रुटि पाई गयी थी, उन आवंटनों को सुप्रीम कोर्ट द्वारा रद्द कर दिया गया था, चाहे वह संघ द्वारा स्थापित स्क्रीनिंग कमेटी की सिफारिशों पर किए गए आवंटन हो या और कानून, कोयला राष्ट्रीयकरण अधिनियम में संशोधन के अभाव में हुई आवंटन हो। जिस नीलामी के बाद, परिणाम विनाशकारी थे। जिसमें कई असफल हुए और उनमें से कुछ सफल भी हुए थे; जाहिर तौर पर राजनीतिक कारणों के लिए उनकी बोलियां रद्द कर दी गई थीं। नीलामी के लिए अभी तक एक सौ से ज्यादा कोयला ब्लॉक लगाए जाने हैं। निवेश का माहौल कम हो चुका है, शायद ही कोई खरीदार हो। कुछ नीलामियों के कारण, बोली मापदंडों को बीच में परिवर्तित करने की मांग की गई थी। ज्यादातर नीलामी विभिन्न कारणों से मुकदमेबाजी में फंस गई थी। आउटपुट का सामना करना पड़ा कोयला का एकमात्र वैकल्पिक स्रोत आयात करना, उस समय महंगा विकल्प था, जो प्रतिस्पर्धा को प्रभावित करता था। उभरती हुई अर्थव्यवस्था में अगर सत्ता की कोई मांग नहीं है, तो अर्थव्यवस्था विकास पक्षाघात से ग्रस्त है। कोयला ब्लॉकों की नीलामी और इसके परिणामों ने एनपीए में योगदान दिया।

मीडिया सनसनी खबरों को पसंद करती है। सीएजी के विदेशी निष्कर्ष आकस्मिक थे, वे सुने बिना जवाब चाहते थे। विवाद है कि नीति के आधार पर स्पेक्ट्रम आवंटन किए गए थे, कोई खरीदार नहीं था। उनके लिए राजस्व का नुकसान, भले ही प्रकल्पित हो अपर्याप्त था। उन्हें यह नहीं पता था कि किसी भी नीति के नुस्खे का उद्देश्य उपभोक्ता को सस्ती और गुणवत्ता वाली सेवा है, जो कि सरकार को समृद्ध बनाने के लिए दुग्ध गायों के रूप में माना जाता है। इस तरह से दोनों सरकार और उद्योग को भुगतना करना पड़ेगा। सिर्फ अगर उद्योग के उपभोक्ता को लाभ होगा, विपक्ष अपनी नाक से परे नहीं देखना चाहता था, क्योंकि राजनीति सब से ऊपर थी। किसी ने भी बुनियादी आधार नहीं पाया कि संसाधनों की कम लागत वाली आवंटन से उद्यमियों को कुशल सस्ती सेवा मुहैया कराने की इजाजत होगी और अगर उद्योग को लाभ होगा तो सरकार को भी लाभ होगा। दूरसंचार क्षेत्र में, यह ऑपरेटर के मुनाफे को साझा करेगा। सरकार अन्य तरीकों से लाभ में थी: निजी क्षेत्र के निवेश में वृद्धि, अधिक एफडीआई, अगर अनुमेय, रोजगार सृजन, हमारे कर लगाने के शासन के जरिये राजस्व में वृद्धि।

प्रकल्पित हानि सुखियों में रहा, लेकिन प्रस्तावित आर्थिक मॉडल अर्थव्यवस्था के लिए विनाशकारी था। एकमात्र आर्थिक मॉडल जो काम करेगा, वह राज्य के लिए निजी क्षेत्र की समृद्धि में हिस्सा लेना है। एक अति उत्साही कैंग, गैर-जिम्मेदार मीडिया, अदूरदर्शी विपक्ष और सर्वोच्च न्यायालय के फैसले, ने भारत की प्रगति पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। सीएजी, मीडिया, विपक्ष और न्यायालय को यह एहसास कराना होगा कि ऐसी गलतियों से हमारा भविष्य अधिकारमय हो सकता है।

### इससे संबंधित तथ्य

#### स्पेक्ट्रम क्या है?

स्पेक्ट्रम, 'इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम' का लघु रूप है। स्पेक्ट्रम उस विकिरण ऊर्जा को कहते हैं, जो पृथ्वी को घेरे रहती है। इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन (ईएमआर-Electro Magnetic Radiation) का मुख्य स्रोत सूर्य है। साथ ही, यह ऊर्जा तारों और आकाशगंगाओं से तथा पृथ्वी के नीचे दबे रेडियोएक्टिव तत्वों से भी मिलती है।

#### इस्तेमाल?

- एक वेव या तरंग की लंबाई, उसकी फ्रिक्वेंसी (वेवलेंथ या साइकल प्रति सेकंड) और उसकी ऊर्जा से इसका इस्तेमाल तय होता है।
- रेडियो वेव तुलनात्मक रूप से काफी लंबे होते हैं। इनकी वेवलेंथ 1 किलोमीटर से लेकर 10 सेंटीमीटर तक की होती है। इसकी फ्रिक्वेंसी भी 3 किलोहर्ट्ज (3,000 साइकिल प्रति सेकंड) से लेकर 3 गीगाहर्ट्ज (3 अरब साइकिल प्रति सेकंड) तक के बीच होती है। इसे माइक्रोवेव्स के नाम से भी जाना जाता है। वहीं, बिजली के मामले में वेव की लंबाई कई-कई किलोमीटर तक की होती है।
- सेंटीमीटर और मिलीमीटर की रेंज वाले माइक्रोवेव्स की फ्रिक्वेंसी 300 गीगाहर्ट्ज तक की हो सकती है। इसके अलग-अलग प्रकार के इस्तेमाल को देखते हुए इसे अलग-अलग नामों से पुकारा जाता है। खाना पकाने वाले माइक्रोवेव में सैकड़ों वॉट बिजली का इस्तेमाल आरएफ वेवलेंथ को पैदा करने में होता है।
- ये वेवलेंथ 32 सेमी (915 मेगाहर्ट्ज) से लेकर 12 सेमी (2.45 मेगाहर्ट्ज) तक के होते हैं। छोटी ऊर्जा स्रोतों वाले उपकरणों से पैदा होने वाले माइक्रोवेव का इस्तेमाल संचार के साधनों के रूप में होता है और ये काफी कम ऊर्जा पैदा करते हैं।
- इन्फ्रारेड वेव छोटी होती हैं और वे काफी गर्म होती हैं। लंबी दूरी वाले इन्फ्रारेड बैंड्स का इस्तेमाल रिमोट कंट्रोल के लिए होता है। साथ ही, इनका इस्तेमाल बहुत कम गर्मी पैदा करने वाले बल्बों में होता है।
- 700-400 नैनोमीटर के वेवलेंथ (करीब 430-750 टेराहर्ट्ज) का इस्तेमाल सफेद रोशनी पैदा करने के लिए होता है।
- छोटी वेवलेंथ से अल्ट्रावायलेट किरणों का निर्माण होता है, जो आपको हानि पहुंचा सकती हैं। समुद्र के किनारे की धूप में 53 फीसदी इन्फ्रारेड, 44 फीसदी दिखाई देने वाली रोशनी और 3 फीसदी अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं।

- कुछ छोटी वेव को एक्सरे कहते हैं और सबसे छोटी को गामा किरणें कहते हैं, जिनका इस्तेमाल चिकित्सा और उद्योगों में होता है।
- आरएफ स्पेक्ट्रम का सबसे फायदेमंद इस्तेमाल दूरसंचार और इंटरनेट में होता है। दूरसंचार और ब्रॉडबैंड के लिए 700-900 मेगाहर्ट्ज की छोटी फ्रिक्वेंसी काफी फायदेमंद होती हैं। इससे लंबी दूरी तय की जा सकती है और वह भी बिना किसी दिक्कत के। रेडियो तरंगों को सबसे ज्यादा असर भाप और आयन से होता है।
- साथ ही, इन पर सोलर फ्लेयर और एक्सरे किरणों के विस्फोट का भी असर होता है। साथ ही, पहाड़ों की वजह से भी रेडियो तरंगों से संचार में काफी असर पड़ सकता है। छोटी फ्रिक्वेंसी मकानों और पेड़ों को भी पार कर सकती हैं। साथ ही, ये पहाड़ों के किनारे से भी निकल सकती हैं।
- बड़ी फ्रिक्वेंसी को वातावरण वापस प्रतिबिंबित या सोख सकता है। उन पर दूरी और वारिश का भी असर होता है। छोटी फ्रिक्वेंसी के नेटवर्क के लिए ज्यादा टावर की जरूरत होती है।

#### 2जी-3जी-4जी या 5-जी

- ये सभी मोबाइल फोन में तकनीकी विकास के अलग-अलग चरण हैं।
- 1जी के एनालॉग वायरलेस की शुरुआत 1980 के दशक में हुई थी, जिसका इस्तेमाल कार फोन में होता था।
- 2जी 1990 के दशक में जीएसएम को अपने साथ लेकर आया आया और इसके साथ सीडीएमए भी आया।
- भारत में 2008 में शुरू हुए 3जी में डाटा का हस्तांतरण तेजी से होता है और नेटवर्क भी अच्छा होता है।
- अब भारत में 4जी की तैयारी चल रही है और कुछ दूरसंचार कंपनियों ने अपने उपभोक्ताओं को यह सेवा देनी शुरू कर दी है, लेकिन अभी इसका व्यापक प्रसार नहीं हुआ है। जबकि विश्व के अधिकांश विकसित देश 5जी तकनीक अपनाने की दिशा में काम कर रहे हैं।
- 2जी या 3जी स्पेक्ट्रम में कोई अंतर नहीं है। केवल सरकार के नियमन और इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशंस यूनियन (आईटीयू) के सदस्य देशों के बीच बेहतर तारतम्यता के तहत इसके लिए अलग स्पेक्ट्रम घोषित किया गया है। दोनों नेटवर्क 800-900 और 1800-1900 मेगाहर्ट्ज पर काम करते हैं और कर सकते हैं।
- फिनलैंड, आइसलैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, थाईलैंड, वेनुजुएला, डेनमार्क और स्वीडन में 900 मेगाहर्ट्ज (2जी स्पेक्ट्रम) पर ही 3जी नेटवर्क मौजूद है।

### संभावित प्रश्न

दूरसंचार लाइसेंस और कोयला ब्लॉक आवंटन को रद्द करने के अदालत के फैसले से एनपीए संकट बढ़े थे। जिससे एक अति उत्साही कैंग, गैरजिम्मेदार मीडिया ने भारत की प्रगति को काफी नुकसान पहुंचाया है। इस कथन का विश्लेषण कीजिये। **NPA crisis was accentuated by court judgments cancelling telecom licenses and coal block allocations. An overzealous CAG, irresponsible media hurt India's progress. Analyze this statement.** (200 words)